संख्या : 851/IV(2)-श0वि0-2015-82(सा0)14

प्रेषक.

डी०एस० गर्ब्याल, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 25 जुलाई, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015–16 में नगर निगम, देहरादून को अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय.

11.

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून के पत्रांक—81 / 51 / 015, दिनांक 10.02.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम, देहरादून के क्षेत्रान्तर्गत "कन्डौली, चिडोवाली में मंदािकनी विहार सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के पास नगर निगम की भूमि पर पार्क निर्माण कार्य" हेतु प्रस्ताव / आगणन उपलब्ध कराते हुए अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, देहरादून को प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु टी०ए०सी० (वित्त विभाग) द्वारा संस्तुत कुल ₹ 19.63 लाख (रूपये उन्नीस लाख तिरेसठ हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

ा. उक्त धनराशि कुल ₹19.63 लाख (रूपये उन्नीस लाख तिरेसठ हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निगम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹18.11 लाख निर्माण कार्यों पर एवं ₹1.52 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार क्रय की जाने वाली सामग्री पर व्यय किया जायेगा।

ाा. स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु स्वीकनिर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

IV. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

v. सभी निर्माण कार्य समय—समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

VI. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

VII. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

VIII. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

मुख्य सन्विव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक IX. 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गढ़ित करते समय का कडाई से पालन किया जाए।

उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो X.

उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा XI. ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

धनराशि का दिनांक 31—3—2016 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का XII.

विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत— 191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—'20 सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता' के नामे ₹15.51 लाख, के अनुदान सं0—30 के लेखाशीर्षक— 2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास— आयोजनागत— 191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डी को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—'42 अन्य व्यय के नामे ₹3.53 लाख, तथा के अनुदान सं0—31 के लेखाशीर्षक— 2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—191— स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डी को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—'20 सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता' के नामे ₹0.59 लाख डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा०संo— 166/xxvII(2)/2015, दिनांक 16.07.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी-s...1507130241..., s...1507300222 एवं s. 1507 3102 2.3. के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

> भवदीय. (डी०एसं० गर्ब्याल) सचिव।

संख्या—<sup>85</sup>/ (1)/IV(2)-शा0वि0—2015, तद्दिनांक। प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) / महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।

निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी / शहरी विकास मंत्री जी। 2.

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी। 3.

जिलाधिकारी, देहरादून। 4.

वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23—लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।

वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

7. वित्तं अनुभाग-2/संयुक्तं निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

्र. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।

9. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।

10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।

11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

्रियं \_\_\_\_\_ ( एच०पी० तिवारी ) अनु सचिव।